Need to implement peace accords with insurgent groups of North East in a time-bound manner-Laid

श्री दिलीप शइकीया **(**दारंग**-**उदालगुड़ी**) :** देश के पूर्वोत्तर राज्यों में 200 से अधिक जनगोष्ठिय समूह हैं । पूर्वोत्तर क्षेत्र ने पिछले कई दशकों में अस्थिर, विषम परिस्थितियों, अलग-अलग विचारधारा के समूहों ने कईं दशकों तक आंदोलन देखा है । 2014 के बाद से यहाँ की तकदीर और तस्वीर दोनों बदली

है । माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूर्वोत्तर को हमेशा से प्राथमिकता दी है और वहां के लोगों को यह विश्वास दिलाया कि विकास के लिए आंदोलन या विवाद की नहीं बल्कि सहयोग और परिश्रम की जरुरत है । मोदी जी के नेतृत्व में हमने पिछले 5 वर्षों में विभिन्न संगठनों के साथ 12 ऐतिहासिक समझौते किये हैं, जिनके कारण आज पूर्वोत्तर के बड़े हिस्से में शांति की स्थापना हुई है । 2014 में मोदी सरकार आने के बाद असम में हिंसक घटनाओं में 87% की कमी आई है । मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए वर्ष 2014-24 तक 4 लाख करोड़ रू. से भी अधिक की राशि खर्च की है । मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में उग्रवादी संगठनों के साथ हमारी सरकार द्वारा किये गए ऐतिहासिक समझौतों को समयबद्ध तरीके से क्रियान्वित किया जाए और स्थायी शान्ति स्थापित करने की दिशा में और भी ठोस कदम उठाये जाएँ ।